



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 368]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 1983/भाद्र 2, 1905

No. 368]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 1983/BHADRA 2, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)
आवेदन

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1984

का. आ. 615(अ) :—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (ख) के साथ पठित धारा 45 की उप-धारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 45 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए आवेदन-पत्र पर विचार करने के बाद वधीष सहकारी बैंक लि., गलाड, तम्रगई (जिसे इसके पश्चात् सहकारी बैंक कहा गया है) के सम्बन्ध में एतद्वारा 16 अगस्त, 1983 को बैंक का कारोबार बन्द होने से लेकर, 15 फरवरी, 1984 तक और उस दिन को मिलाकर अधिस्थगन आदेश जारी करती है, जिसके अनुसार अधिस्थगन आदेश की अवधि के दौरान सहकारी बैंक के विरुद्ध सभी कार्य-वाहियों का शुरू किया जाना अथवा शुरू की गई कारवाहियों को जारी रखना स्थगित किया जाता है किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार के अधिस्थगन का किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार

द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

2. केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि उसे स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान यह सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं देगा, किसी अग्रिम का नवीकरण नहीं करेगा, बैंक की किसी परसम्पत्ति का अन्या संक्रामण अथवा निपटान नहीं करेगा, किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा अथवा अपने दायित्वों और देनदारियों के सम्बन्ध में अथवा अन्यथा किसी प्रकार की अदायगी नहीं करेगा अथवा अदायगी करना स्वीकार नहीं करेगा अथवा किसी प्रकार का समझौता अथवा टह्राव नहीं करेगा किन्तु वह निम्नलिखित तरीके से और निम्नलिखित सीमा तक यथास्थिति अदायगियां अथवा स्वर्च करेगा :—

(1) प्रत्येक बचत बैंक अथवा चालू खाते अथवा किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले किसी अन्य जमा खाते में शेष रकम में से निम्नलिखित राशि तक :—

जमा रकम
50/- रुपये तक
50/- रुपये
से अधिक

देय रकम
पूरी
जमा का 10 प्रतिशत अथवा
50/- रुपये जो भी अधिक हो

बशर्त कि अदा की गई रकम की कुल सीमा किसी एक व्यक्ति (किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त खाते में नहीं) के नाम से खाते में जमा कुल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक अथवा 50/- रुपये, इनमें जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा न हो :

यह भी शर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई रकम अदा नहीं की जाएगी जो किसी प्रकार से सहकारी बैंक का कर्जदार हो ;

- (2) ऐसे किसी बैंक ड्राफ्ट, पे-आर्डर अथवा चेकों की राशि जो सहकारी बैंक द्वारा उग तारीख को जारी कर दिए गए हैं जिसका उस तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है जिसको अधिस्थगन आदेश लागू होता है ;
- (3) 16 अगस्त, 1983 को अथवा उससे पूर्व भुगतान के लिए प्राप्त हुण्डियों की राशि चाहे वे उस तारीख से पहले, उस तारीख को या उस तारीख के बाद बसूल की गई हों ;
- (4) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी सहकारी बैंक के द्वारा उसके अथवा उसके विरुद्ध वायर किए गए मुकदमों, अपील अथवा सहकारी बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध नी गई डिमंडी या बैंक को मिलने वाली किसी रकम को बसूल करने के सम्बन्ध में करता आवश्यक हो ;

बशर्त कि प्रत्येक मुकदमों, अपील अथवा डिमंडी के सम्बन्ध में दिए जाने वाले व्यय की रकम 250/- रुपये से अधिक हो, तो खर्च करने में पहले भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति ली जाएगी ; और

- (5) किसी अन्य मद पर कोई व्यय, जहां तक कि वह व्यय सहकारी बैंक के विचार में बैंक का दैनिक प्रशासन चलाते के लिए करता अनिवार्य हो ;

बशर्त कि जहां किसी एक कैलेंडर मास में किसी मद पर किया गया कुल खर्च अधिस्थगन आदेश से पहले के छः कैलेंडर मासों में उग मद पर किए गए औसत मासिक व्यय से बढ़ जाता हो, अथवा उग अधि के दौरान जहां उस मद पर कोई व्यय नहीं किया गया हो और उस प्रकार किया जाने वाला व्यय 250/- रुपये से बढ़ जाए तो उस प्रकार का व्यय करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित रूप में अनुमति ली जाएगी ।

3. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह भी निदेश देती है कि इस सहकारी बैंक की स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान :—

- (क) यह सहकारी बैंक निम्नलिखित और अदायगीयां कर सकेगा, अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के बदले महाराष्ट्र सरकार, अथवा महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लि., भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किन्हीं सहायक बैंकों या किसी अन्य बैंक द्वारा सहकारी बैंक को किए गए ऋणों अथवा अग्रिमों, जो अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने की तारीख को चुकाए जाने शेष थे, की वापसी अदायगी के लिए आवश्यक हों ।

- (ख) सहकारी बैंक को पूर्वोक्त अदायगीयां करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लि. अथवा किसी अन्य बैंक के साथ अपने खाते चलाने की अनुमति दी जाएगी ।

परन्तु इस आदेश का ऐसा कोई वाशय नहीं होगा कि इस सहकारी बैंक को किसी रकम के दिए जाने से पहले महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लि. अथवा वैसे किसी अन्य बैंक को इस सम्बन्ध में अपने आपको आवश्यक करता होगा कि इस आदेश द्वारा लगाई गई शर्तों का इस बैंक द्वारा पालन किया जा रहा है ।

- (ग) यह सहकारी बैंक, उन हुण्डियों को, जो बसूल न की गई हों, उनको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर लौटा सकेगा यदि इस सहकारी बैंक का उन हुण्डियों पर कोई अधिकार अथवा हक न हो अथवा वैसे हुण्डियों में उनका कोई हित न हो ।
- (घ) सहकारी बैंक ऐसे मान अथवा प्रतिभूतियों को जो इन (निक) के पास किसी ऋण, नकद, कर्ज अथवा डीवर-ड्राफ्ट के बदले गिरवी, दृष्टि-बन्धक अथवा बन्धक रक्की गई हों अथवा अन्तर्गत प्रमाप्ति की गई हो, निम्नलिखित मामलों में छोड़ अथवा दे सकेगा :—

- (1) किसी ऐसे मामले में जहां यथास्थिति ऋणकर्ताओं से मिलने वाली सारी रकम सहकारी बैंक द्वारा बिना शर्त प्राप्त की गई है ; और
- (2) किसी अन्य मामले में, उस सीमा तक की रकम जिसकी आवश्यक अथवा गन्ताव हो, निर्दिष्ट अनुपातों से नीचे अथवा उन अनुपातों से नीचे, जो अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने से पहले लागू थी, इसमें जो भी ऊंचे हों, उक्त माल और प्रतिभूतियों पर माजिन के अनुपातों को कम किए बिना ।

[सं. 8-11/83-ए. सी. 1]

अमर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

ORDER

New Delhi, the 16th August, 1983

S.O. 615(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45, read with clause (zb) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering the application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of the said section 45, hereby makes an order of moratorium in respect of the Dadhich Sahakari Bank Ltd., Malad, Bombay, hereinafter referred to as the Co-operative Bank; for the period from the close of business on the 16th August, 1983 upto and inclusive of the 15th February, 1984 staying the

commencement or continuance of all actions and proceedings against the Co-operative Bank during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Government of Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.

2. The Central Government hereby directs that, during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank shall not, without the prior permission in writing of the Reserve Bank of India, grant any loan, make or renew any advance, alienate or dispose of any assets of the bank, incur any liability, make any investment or make or agree to make any payment, whether in discharge of its liabilities or obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except making of payments, or incurring of expenditure, as the case may be, to the extent and in the manner provided hereunder :—

(i) Out of the balance in every savings banks or current account or in any other deposit account, by whatever name called, a sum not exceeding the following :—

Deposit amount	Amount payable
Upto Rs. 50	In full
About Rs. 50	10 per cent of the deposit or Rs. 50 whichever is higher

Provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed 10 per cent of total deposit, or Rs. 50 whichever is higher :

Provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the Co-operative Bank in any way;

(ii) the amounts of any drafts or pay orders or cheques issued by the Co-operative Bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

(iii) the amounts of the bills received for collection on or before 16th August, 1983 whether realised before, on or after that date;

(iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against, or decree obtained by or against, the Co-operative Bank, or for realising any amounts due to it :

Provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree is in excess of Rs. 250, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred; and

(v) any expenditure on any other item insofar as it is in the opinion of the Co-operative Bank necessary for carrying on the day-to-day administration of the Co-operative Bank :

Provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or, where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds the sum of Rs. 250, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

3. The Central Government hereby also directs that, during the period of moratorium granted to it, the Co-operative Bank—

(a) may make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advance granted against Government securities or other securities to the Co-operative Bank by the Government of Maharashtra or the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium come into force;

(b) may operate its accounts with the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or with any other bank for the purpose of making the payments aforesaid :

Provided that nothing in this order shall be deemed to require the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or such other bank to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Co-operative Bank ;

(c) may return any bills which have remained unrealized to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the Co-operative Bank has no right or title to, or interest in such bills;

(d) may release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft, in the manner and to the extent—

(i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the Co-operative Bank, unconditionally, and

(ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions, or the proportions

which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[No. 8/11/83-AC]

AMAR SINGH, Under Secy.